draw your attention that I have given a notice of privilege motion against M/s. Reliance Industries for attributing my statement as well as Mr. Gurudas Das Gupta's statement as "malicious statement." He has also stated that my brother is on the Board of Directors of the Bombay Dyeing. This is totally frivolous and mischievous. My brother is not on the Board of Directors. Some four years back, he was an employee of the Bombay Dyeing. But he resigned as soon as I started attacking M/s. Reliance Industries for their nefarious activities. Mr. Vice-Chairman, I would request through you the Chairman that my privilege notice should be sent to the Privileges Committee and we should haul up the Reliance Industries and its proprietor, Mr. Ambani.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Your privilege notice is under the consideration of the Chairman.

DEMAND FOR ALLOTMENT OF EDIBLE OIL TO MAHARASHTRA

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to raise a very important issue which concerns the common man. I am very sorry to say that Maharashtra State has not received a single drop of edible oil for the month of December. As far as my knowledge goes, up to 9th January, 1991 not a single drop of edible oil has been given. The public distribution system is completely in chaos because of non-supply of edible oil. I am told that even in Andhra Pradesh the same situation is prevailing. I do not understand why the Congress-ruled States have not been allotted edible oil stocks. The prices are going sky-high. In spite of that this Government has not given a single drop of edible oil. Earlier they were giving about 12,000 tonnes of oil every month. I urge upon the Government to give it to Maharashtra immediately so that it can be distributed through the public distribution system. Otherwise, there will be a chaos and the people will agitate on this issue. I warn the Government that if edible oil is not given in time, then the Government will have to face a crisis.

REFERENCE TO THE KILLING OF AN IPS OFFICER IN A BANK DOCOITY IN DHANBAD

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार): अभी-अभी हम लोगों ने भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहां पर पारित किया। इस संबंध में काफी चर्चाएं हुई। एक बहुत आवश्यक बात की ओर मैं सरकार का ध्यान आपकी अनुमति से दिला रहा हूं। मंत्री महोदय इधर देखें। वह जरूरी है चूंकि बैंक के ऊपर इतनी चर्चाएं हुई। मैंने 2-3 दिन पहले इस सदन में सरकार का ध्यान धनबाद में एक बैंक डकैती के तहत वहां के एक बहादुर आई०पी०एस० अधिकारी एस०पी० रणधीर वर्मा की आतंकवादियों द्वारा गोली से हत्या कर देने के बारे में दिलाया था। बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार को लिखा कि इस में सी०बी० आई० इन्क्वायरी होनी चाहिए। यह केवल एक बहादुर अधिकारी की हत्या नहीं थी, इसमें बैंक की सुरक्षा का सवाल था, इसमें सरकार की लापरवाही का सवाल भी था, इसमें चूंकि पंजाब से आतंकवादियों का फैलाव पूरे देश हो रहा है अतः इसका भी सवाल था, इसमें यह भी सवाल था कि बिहार सरकार ने भारत सरकार को लिखा है। बिहार सरकार के जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं श्री रामचन्द्र ? श्री डी० एम० सहाय आदि, ये तहकीकात कर रहे हैं लेकिन साथ साथ भारत सरकार का भी अपना कर्तव्य होता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा चूंकि वे एक इतने बड़े कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे अतः इसके बारे में भारत सरकार की चुप्पी अभी तक मुझे समझ में नहीं आती है। इससे पूरे देश में डिमारलाजेशन छा रहा है। देश के सारे पत्रों में फ्रंट पेज में इस बारे में खबरें निकाली हैं। मैंने सदन के

[श्री शंकर दयाल सिंह]

नेता श्री यशवन्त सिन्हा और श्री सुबोध कान्त सहाय से कहा। दोनो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और माननीय उप मंत्री श्री दिविग्जय सिंह जी भी उस अधिकारी और उस घटना के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि सरकार की ओर से आज बयान होना चाहिए कि श्री रणधीर वर्मा जिनकी बैंक लूटते समय आतंकवादियों द्वारा हत्या की गयी है उनके संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और सी०बी०आई० से इन्क्वायरी कराने जा रही है या नहीं कराने जा रही है।

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश): महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है। सी०बी०आई० की इन्वायरी कोई बड़ी बात नहीं है। एक बहादुर अधिकारी की हत्या हुई है उसकी जांच सी०बी० आई० से सरकार को करानी चाहिए। माननीय संसदीय मामलों के मंत्री यहां उपस्थित हैं वे कृपया आश्वासन दें।

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री और विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): महोदय, मरने वाले अधिकारी मेरे जीवन के 20-25 वर्षों के निजी मित्र रहे हैं। मैंने उनके साथ अपने जीवन के 20-25 वर्षों को गुजारा है। जो बात माननीय सदस्य श्री शंकर दयाल और जोगी साहब ने कहीं है उसमें सरकार पूर्ण रूप से चीजों के बारे में जानकारी रख रही है। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार कभी भी सी०बी०आई० की इंक्वायरी से हिचकेगी नहीं। अभी ऐसा लगता है कि करीब करीब सारी सही जानकारी राज्य सरकार के लोगों को मिल रही है। हम सारे लोग निजी तौर से भी उस हत्या से दुखी हैं। बैंक को लूटते समय वह पुलिस अधिकारी मारा गया है इससे वित्त मंत्रालय में रहने की वजह से और भी मेरा निजी नुक्सान हुआ है और दूसरों के लिए एक मिसाल भी पेश हुई है। अपने कर्तव्यों के लिए जिन लोगों ने जानें गंवायी, रणधीर वर्मा उसी श्रेणी में आ गये हैं। मैं दोनों माननीय सदस्यों को सरकार की तरफ से बताना चाहूंगा कि हम लोग उस मामले की पूरी जानकारी रख रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो सी.बी.आई. की इंक्वायरी हम अवश्य कराएंग।

THE RESERVE BANK OF INDIA (AMENDMENT) BILL, 1990—

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Now, there is a small amendment Bill to be taken up. We shall take up that Bill.

SHRI SUNIL BASU RAY (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, I want to make only one point before this Bill is taken up.

Most of the banks remain undefended. The question of defence has not been met by the hon. Minister. I want an assurance from the Minister that all the banks, their offices, situated in interior rural areas will be properly defended.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE AND DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DIGVIJAY SINGH): Sir, I beg to move:

"That the following amendment made by the Lok Sabha in the Reserve Bank of India (Amendment) Bill, 1990, be taken into consideration, namely:—

Clause—1

Page 1, lines 3 and 4,—

for "(Amendment) Act, 1990"

substitute "(Second Amendment) Act, 1991"

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DIGVIJAY SINGH): Sir, I beg to move: